बिहार में सुशासन और स्थानीय विकास विषय पर शिक्षाविद, नौकरशाह और उद्यमियों ने की सार्थक चर्चा

संवाददाता । एजुकेशनल न्यूज

पटना । चन्द्रगुप्त इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना ने "सामाजिक नीतियां और प्रबंधन" विषय पर जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। 17 एवं 18 जून को सीआईएमपी कैंपस में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों संस्थाओं के बीच बिहार सरकार के चीफ सेक्रेट्री ब्रजेश मेहरोत्रा की उपस्थिति में एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के तहत साझा शोध कार्यक्रमों के अलावा छात्र-छात्राओं का एक संस्थान से दूसरे संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियों हेतु आना-जाना संभव होगा।

कार्यक्रम के दूसरे दिन पहले सत्र में "स्वास्थ्य, शिक्षा एवं वैश्विक स्तर समेत भारत में गरीबी उन्मूलन में नीतियों का महत्व" विषय पर अलग-अलग संस्थानों से आए विशेषज्ञों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। 'मतदाता एवं चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही' विषय पर जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वार्ल्स हांक्ला ने पेरू में किए अपने अध्ययन के ज़रिए समझाने का प्रयास किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च का जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने (रिकॉलिंग) या पुनः जनता द्वारा चुने में बड़ी भूमिका होती है। जॉर्जिया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रो.अंजलि थॉमस ने सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच को लेकर मुंबई के 153 झुग्गियों में किए अपने शोध अध्ययन को प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज के सबसे वंचित लोगों के

लिए पीने का पानी जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने में सरकारी तंत्र और राजनैतिक नेतृत्व समायोजन के बेहतर परिणाम को दर्शाया।

आईआईपीए के प्रो. वी एन आलोक ने स्थानीय निकायों में जमीनी स्तर पर आ रही दिक्कतों में नीतियों का क्या योगदान है, इस पर प्रकाश डाला। पंचायतों और नगर निकायों को मजबूत करने के लिए उन्होंने केन्द्रीय वित्त आयोग के माध्यम से सीधे फण्ड उपलब्ध करवाने पर बल दिया।

डॉ. सायन बनर्जी, टेक्सस टेक यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रस्तुति में बिहार में महिला आरक्षण के महत्व और प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला। हेइफर इंटरनेशनल इंडिया की डॉ.अनामिका प्रियदर्शनी ने कहा कि किशोरों एवं युवाओं को पुरुषवादी सोच के दुष्प्रभावों से दूर करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि कम उम्र से ही लड़कों को लिंग से जुड़े मुद्दों के बारे में प्रशिक्षण के ज़रिए सही जानकारी देना शुरू किया जाए तो ऐसे दुष्प्रभावों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इस सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ प्रदीप कुमार चौधरी ने की। इसके बाद का सत्र जमीनी स्तर पर नीतियों के प्रभाव, पर्यावरण परिवर्तन एवं सतत कृषि व उद्योगों के बिहार में विकास पर केन्द्रित रहा। सीआईएमपी के व्याख्यातागण डॉ. एस सेनापति एवं डॉ. डी. सामंता, चन्दन झा, सीईईडब्ल्यू, डॉ. इन्द्रजीत कुमार, आईईजी, नई दिल्ली, और पटना विश्वविद्यालय के प्रमीत कुमार विनीत ने बिहार के अलग अलग हिस्सों में किए अपने शोध अध्ययनों को लेकर डॉ. उत्सव कुमार की अध्यक्षता में अपनी प्रस्तुतियां दी। अंतिम तकनीकी सत्र में 'बिहार में उद्यमिता और चुनौतियां' विषय पर बिहार के कई युवा उद्यमियों ने विस्तार से अपनी बातें रखी। इस सत्र का संचालन सीआईएमपी की शोधार्थी प्रिया नाथ ने किया। समापन सत्र में दो दिनों तक विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा-परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं को सीआईएमपी के प्राध्यापक डॉ. एस. सेनापति संक्षेप में साझा किया। सीआईएमपी के निदेशक प्रो. राणा सिंह, प्रो. वार्ल्स हैंक्ला, प्रो. अंजली थॉमस, डॉक्टर सायन बैनर्जी और डॉक्टर डी. सामंता, सीआईएमपी ने कॉन्फ्रेंस के दौरान मिली जानकारियों को आधार बनाकर बिहार में सुशासन और स्थानीय विकास को और सशक्त बनाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। सीआईएमपी के सीएओ कुमोद कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

बिहार में सुशासन और स्थानीय विकास विषय पर शिक्षाविद, नौकरशाह और उद्यमियों ने की सार्थक चर्चा

जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सीआईएमपी द्वारा सामाजिक नीति एवं विकास के मुद्दे पर आयोजित दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक संपन्न

संजीव कुमार

पटना/संवाददाता। चन्द्रगुप्त इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना ने ह्नसामाजिक नीतियां और प्रबंधनह्न विषय पर जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। 17 एवं 18 जून को सीआईएमपी कैंपस में आयोजित इस कांफ्रेंस के दौरान दोनों संस्थाओं के बीच बिहार सरकार के चीफ सेक्रेट्री ब्रजेश मेहरोत्रा की उपस्थिति में एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के तहत साझा शोध कार्यक्रमों के अलावा छात्र-छात्राओं का एक संस्थान से दूसरे संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियों हेतु आना-जाना संभव होगा।

कार्यक्रम के दूसरे दिन पहले सत्र में ह्नस्वास्थ्य, शिक्षा एवं वैश्विक स्तर समेत भारत में गरीबी उन्मूलन में नीतियों का महत्वह्न विषय पर अलग-अलग संस्थानों से आये विशेषज्ञों ने प्रस्तुतियां दीं। 'मतदाता एवं चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही' विषय पर जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चार्ल्स हांक्ला ने पेरू में किए अपने अध्ययन के जरिए समझाने का प्रयास किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च का जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने (रिकॉलिंग) या पुनः जनता द्वारा चुने में बड़ी भूमिका होती है। जॉर्जिया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर अंजलि थॉमस ने सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच को लेकर मुंबई के 153 झुग्गियों में किए अपने शोध अध्ययन को प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज के सबसे वंचित लोगों के लिए पीने का पानी जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने में सरकारी तंत्र और राजनैतिक नेतृत्व समायोजन के बेहतर परिणाम को दर्शाया। आईआईपीए के प्रो. वीएन आलोक ने स्थानीय निकायों में जमीनी स्तर पर आ रही दिक्कतों में नीतियों का क्या योगदान है, इसपर प्रकाश डाला। पंचायतों और नगर निकायों को मजबूत करने के लिए उन्होंने केन्द्रीय वित्त आयोग के माध्यम से सीधे फण्ड उपलब्ध करवाने पर बल दिया।

डॉ. सायन बनर्जी, टेक्सस टेक यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रस्तुति में बिहार में महिला आरक्षण के महत्व और प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला। हेइफेर इंटरनेशनल इंडिया की डॉ.अनामिका प्रियदर्शनी ने कहा कि किशोरों एवं युवाओं को पुरुषवादी सोच के दुष्प्रभावों से दूर करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि कम उम्र से ही लड़कों को लिंग से जुड़े मुद्दों के बारे में प्रशिक्षण के जरिए सही जानकारी देना शुरू किया जाए तो ऐसे दुष्प्रभावों को काफी हद तक रोका जा सकता है। इस सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ प्रदीप कुमार चौधरी ने की। इसके बाद का सत्र जमीनी स्तर पर नीतियों के प्रभाव, पर्यावरण परिवर्तन एवं सतत कृषि व उद्योगों के बिहार में विकास पर केन्द्रित रहा। सीआईएमपी के व्याख्यातागण डॉ. एस सेनापति एवं डॉ. डी. सामंता, चन्दन झा, सीईईडब्ल्यू, डॉ. इन्द्रजीत कुमार, आईईजी, नई दिल्ली, और पटना विश्वविद्यालय के प्रमीत कुमार विनीत ने बिहार के अलग अलग हिस्सों में किए अपने शोध अध्ययनों को लेकर डॉ. उत्सव कुमार की अध्यक्षता में अपनी प्रस्तुतियां दीं।

अंतिम तकनीकी सत्र में 'बिहार में उद्यमिता और चुनौतियां' विषय पर बिहार के कई युवा उद्यमियों ने विस्तार से अपनी बातें रखी। इस सत्र का संचालन सीआईएमपी की शोधार्थी प्रिया नाथ ने किया।

समापन सत्र में दो दिनों तक विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा-परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं को सीआईएमपी के प्राध्यापक डॉ. एस. सेनापति संक्षेप में साझा किया। सीआईएमपी के निदेशक प्रो. राणा सिंह, प्रो. चार्ल्स हैंक्ला, प्रो. अंजली थॉमस, डॉक्टर सायन बैनर्जी और डॉक्टर डी. सामंता, सीआईएमपी ने कॉन्फ्रेंस के दौरान मिली जानकारियों को आधार बनाकर बिहार में सुशासन और स्थानीय विकास को और सशक्त बनाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। सीआईएमपी के सीएओ कुमोद कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

पंचायतों व नगर निकायों को केन्द्रीय वित्त आयोग से सीधे मिले फंड

पटना (एसएनबी)। चन्द्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना ने सामाजिक नीतियां और प्रबंधन विषय पर जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सीआईएमपी कैंपस में 17 एवं 18 जून को आयोजित इस कॉफ्रेंस के दौरान दोनों संस्थाओं के बीच बिहार सरकार के चीफ सेक्रेट्री ब्रजेश मेहरोत्रा की उपस्थिति में एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के तहत साझा शोध कार्यक्रमों के अलावा छात्र-छात्राओं का एक संस्थान से दूसरे संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आना-जाना संभव होगा।

कार्यक्रम के दूसरे दिन पहले सत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं वैश्विक स्तर समेत भारत में गरीबी उन्मूलन में नीतियों का महत्व विषय पर अलग-अलग संस्थानों से आये विशेषज्ञों ने प्रस्तुतियां दीं। 'मतदाता एवं चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही' विषय पर जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चार्ल्स हांक्ला ने पेरू में किए अपने अध्ययन के जरिए समझाने का प्रयास किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च का जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने (रिकॉलिंग) या पुनः जनता द्वारा चुनने में बड़ी भूमिका होती है। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर अंजलि थॉमस ने सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच को लेकर मुंबई के 153 झुग्गियों में किए अपने शोध अध्ययन को प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज के सबसे वंचित लोगों के लिए पीने का पानी जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने में सरकारी तंत्र और राजनैतिक नेतृत्व समायोजन के बेहतर परिणाम को दर्शाया। आईआईपीए के प्रो. वीएन आलोक ने स्थानीय निकायों में जमीनी स्तर पर आ रहीं दिक्कतों में नीतियों का क्या योगदान है, इसपर प्रकाश डाला। पंचायतों और नगर निकायों को मजबूत करने के लिए उन्होंने केन्द्रीय वित्त आयोग के माध्यम से सीधे फण्ड उपलब्ध करवाने पर बल दिया। डॉ. सायन बनर्जी, टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रस्तुति में बिहार में महिला आरक्षण के महत्व और प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला। हेइफेर इंटरनेशनल इंडिया की डॉ. अनामिका प्रियदर्शनी ने कहा कि किशोरों एवं युवाओं को पुरुषवादी सोच के दुष्प्रभावों से दूर करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि कम उम्र से ही लड़कों को लिंग से जुड़े मुद्दों के बारे में प्रशिक्षण के जरिए सही जानकारी देना शुरू किया जाए तो ऐसे दुष्प्रभावों को काफी हद तक रोका जा सकता है।

- बिहार में 'सुशासन और स्थानीय विकास' विषय पर शिक्षाविद्, नौकरशाहों और उद्यमियों ने की चर्चा
- समझौता : एक संस्थान से दूसरे संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आ-जा सकेंगे सीआईएमपी और जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी

Rashtriya Sahara ! Page No - 03 ! Date - 19-06-2024 !

CIMP, US varsity ink MoU for joint studies on public policy

B K Mishra@timesgroup.com

Patna: The Chandragupt Institute of Management Patna (CIMP) inked an MoU with the Georgia State University, USA at an international conference on public policy and management organised here on Tuesday. The MoU, which aims at promoting collaborative studies on public policy, was signed by the authorities of both the institutions in the presence of state's chief secretary Brijesh Mehrotra.

Participating in the deliberations of the conference, the management experts and social scientists presented their view points on various aspects of policy and service delivery challenges in poverty alleviation, education and health in India and the world.

Discussing the electoral accountability and fiscal accountability in Peru, Charles Hankla of Georgia State University, stated that the scale of funding

TOI

CIMP and Georgia State University, USA, officials at the MoU signing event on Tuesday

on public services by the elected representatives influences their electoral accountability that gets manifested by the voters in the form of recalls and re-election.

Presenting the findings of the study on the access to public services in 153 slums of Mumbai, Anjali Thomas of Georgia Institute of Technology, USA underlined that if both bureaucratic assistance and political coordination work together, it maximizes the chances of better delivery of services like drinking water supply to the people lying in the last echelon of the society.

V N Alok of Indian Institute of Public Administration (IIPA), New Delhi, said that the adoption of the 'top-down approach' in creating local bodies has hindered the growth of grass-root governance. In order to strengthen the PRIs and municipalities, he recommended for the direct allocation of funds to the local bodies from the Union Finance Commission as being done in case of the state governments.

Sayan Banerjee of Texas Tech University, USA, in his presentation, discussed how local gender quota improves the electability of higher tiers. Anamika Priyadarshini of Heifer International India, Pradeep Kumar Chaudhary of JNU, New Delhi, also spoke on the occasion.

Times of India ! Page - 02 ! Date - 19-06-2024 !

बिहार में सुशासन और स्थानीय विकास पर शिक्षाविद, नौकरशाह और उद्यमियों ने की सार्थक चर्चा

पटना। चन्द्रगुप्त इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना ने 'सामाजिक नीतियां और प्रबंधन' विषय पर जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस का आयोजन किया। 17 एवं 18 जून को सीआईएमपी कैंपस में आयोजित इस कांफ्रेंस के दौरान दोनों संस्थाओं के बीच बिहार सरकार के चीफ सेक्रेट्री ब्रजेश मेहरोत्रा की उपस्थिति में एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के तहत साझा शोध कार्यक्रमों के अलावा छात्र-छात्राओं का एक संस्थान से दूसरे संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियों हेतु आना-जाना संभव होगा। कार्यक्रम के दूसरे दिन पहले सत्र में 'स्वास्थ्य, शिक्षा एवं वैश्विक स्तर समेत भारत में गरीबी उन्मूलन में नीतियों का महत्व' विषय पर अलग-अलग संस्थानों से आये विशेषज्ञों ने प्रस्तुतियां दीं। 'मतदाता एवं चुनाव प्रक्रिया में जवाबदेही' विषय पर जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चार्ल्स हांक्ला ने पेरू में किए अपने अध्ययन के ज़रिए समझाने का प्रयास किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च का जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने (रिकालिंग) या पुनः जनता द्वारा चुने में बड़ी भूमिका होती है। जॉर्जिया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर अंजलि थॉमस ने सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच को लेकर मुंबई के 153 झुग्गियों में किए अपने शोध अध्ययन को प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज के सबसे वंचित लोगों के लिए पीने का पानी जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने में सरकारी तंत्र और राजनैतिक नेतृत्व समायोजन के बेहतर परिणाम को दर्शाया। आईआईपीए के प्रो. वीएन आलोक ने स्थानीय निकायों में जमीनी स्तर पर आ रही दिक्कतों में नीतियों का क्या योगदान है, इसपर प्रकाश डाला। पंचायतों और नगर निकायों को मजबूत करने के लिए उन्होंने केन्द्रीय वित्त आयोग के माध्यम से सीधे फण्ड उपलब्ध करवाने पर बल दिया। डॉ. सायन बनर्जी, टेक्सस टेक यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रस्तुति में बिहार में महिला आरक्षण के महत्व और प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला। हेइफेर इंटरनेशनल इंडिया की डॉ.अनामिका प्रियदर्शनी ने कहा कि किशोरों एवं युवाओं को पुरुषवादी सोच के दुष्प्रभावों से दूर करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि कम उम्र से ही लड़कों को लिंग से जुड़े मुद्दों के बारे में प्रशिक्षण के ज़रिए सही जानकारी देना शुरू किया जाए तो ऐसे दुष्प्रभावों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इस सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ प्रदीप कुमार चौधरी ने की। इसके बाद का सत्र जमीनी स्तर पर नीतियों के प्रभाव, पर्यावरण परिवर्तन एवं सतत कृषि व उद्योगों के बिहार में विकास पर केन्द्रित रहा। सीआईएमपी के व्याख्यातागण डॉ. एस सेनापति एवं डॉ. डी. सामंता, चन्दन झा, सीईईडब्ल्यू, डॉ. इन्द्रजीत कुमार, आईईजी, नई दिल्ली, और पटना विश्वविद्यालय के प्रमीत कुमार विनीत ने बिहार के अलग अलग हिस्सों में किए अपने शोध अध्ययनों को लेकर डॉ. उत्सव कुमार की अध्यक्षता में अपनी प्रस्तुतियां दीं।

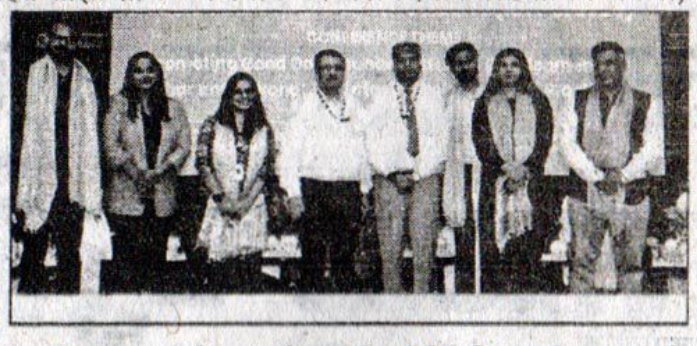

Aaj ! Page No - 08 ! Date - 19-06-2024 !

जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी और सीआईएमपी के बीच एमओयू

पटना/संवाददाता। मंगलवार को सीआईएमपी परिसर में सार्वजनिक प्रबंधन पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के सहयोग से सीआईएमपी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य बिहार और उसके बाहर सुशासन और स्थानीय विकास को बढ़ावा देना है। इस दौरान जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी और सीआईएमपी के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत दोनों शिक्षण संस्थानों द्वारा विभिन्न विषयों पर शोध के साथ-साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शामिल हैं। बिहार के मुख्य सचिव बृजेश मेहरोत्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उनके कर कमलों द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में बिहार के सुशासन मॉडल पर बात की और सतत विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक हितधारक को शामिल करके राज्य में सहभागी दृष्टिकोण से सतत विकास हासिल किया जा सकता है।

Sanmarg ! Page No - 03 ! Date - 19-06-2024 !

सीआइएमपी : बिहार में सुशासन व विकास के मुद्दे पर हुई परिचर्चा

लाइफ रिपोर्टर @ पटना

चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की ओर से सामाजिक नीतियां और प्रबंधन विषय पर जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया. कार्यक्रम के दूसरे दिन के पहले सत्र में 'स्वास्थ्य, शिक्षा एवं वैश्विक स्तर समेत भारत में गरीबी उन्मूलन में नीतियों का महत्व' विषय पर अलग-अलग संस्थानों से आये विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किये. जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर अंजलि थॉमस ने सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच को लेकर मुंबई के 153 झुग्गियों में किये अपने शोध अध्ययन को प्रस्तुत किया.

वहीं चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान व जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे व अंतिम दिन दिन मंगलवार को एमओयू साइन किया गया. मौके पर बिहार सरकार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा भी मौजूद थे.

Prabhat Khabar ! Page - 09 ! Date- 19-06-2024 !